हम अंतर-जनपदीय साम्य को कैसे लागू करते हैं? सुप्रीम कोर्ट के इस सवाल ने हमें हैरान कर दिया था।

अंतरजनपदीय साम्य? हमने दुनिया भर में देखा कि दूसरे क्या करते हैं।

यह उत्तर काफी सरल है - अंतरजनपदीय साम्य को लागू करने के लिए, **भविष्य की पीढ़ियों को कम से कम उतना तो विरासत में प्राप्त करना चाहिए जितना हमने किया था।**

कल्पना कीजिए कि हमें एक कीमती हार मिला है। यदि हम हार को वैसे का वैसा ही रखते हैं, तो ही हमारे बच्चे उसे प्राप्त करेंगे। लेकिन हमें इसे सुरक्षित रखना चाहिए जो एक लागत है जबकि हार कोई आय नहीं पैदा करता है।

इसके बजाय, हम हार बेचने और भूमि में निवेश का फैसला कर सकते हैं। जब तक हम भूमि को ठीक से बनाए रखते हैं, तब तक हमारे पास आय का अधिकार है। प्रत्येक पीढ़ी को भूमि विरासत में मिलेगी और बदले में आय से लाभ होगा।

[रुकें]

भारत में, गोवा जैसे राज्य लोगों और विशेष रूप से भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक ट्रस्टी की तरह खनिजों का मालिक हैं।

खनिज एक साझा विरासत हैं ।खनन प्रभावी रूप से हमारे खनिज संपदा की बिक्री है ।हमें अपने खनिजों के बदले में अधिशुल्क और नीलामी अधिमूल्य मिलता है।

क्या गोवा के बच्चों को हमारे द्वारा पाई गई खनिज संपदा विरासत में मिलेगी? आइए पता लगाते हैं ।

हमारे अनुमानों के लिए, हमने हमारे सबसे बड़े खनिक-वेदांत और सरकारी वित्तीय आंकड़ों के आठ साल के लेखा परीक्षित वित्तीय का इस्तेमाल किया।

हमने पाया कि हमारे द्वारा बेचे जाने वाले खनिजों के हर एक सौ सत्तर रुपये के लिए, खनिक के लिए एक उदार लाभ सहित निष्कर्षण की कुल लागत सत्तर थी। इसलिए, खनिज का मूल्य हमारे लिए एक सौ था।

यदि हमारे खनिजों का मूल्य एक सौ है, तो हमें कितना प्राप्त करना चाहिए?

[जवाब के लिए रुकें]

हां, हमें एक सौ प्राप्त करना चाहिए। शून्य हानि यानि **जीरो लॉस** हमारा लक्ष्य है।

यह पता चला कि एक सौ की कीमत वाले खनिजों के लिए, गोवा सरकार को केवल पांच प्राप्त हुए। यानि हमे पिचानबे का नुक्सान हुआ!

और यहां तक कि हमें प्राप्त पांच को आय और खर्च के अंतर्गत माना गया। **कुल नुकसान।**

[आत्म्सात करने के लिए रुकें]

चूँकि हमने खनिजों का समान रूप से स्वामित्व किया था, हम सभी समान रूप से हार गए । चालीस खनक और उनके साथी अत्यंत अमीर हो गए । जिस राशि को वे गलत तरीके से लेते थे, वह पूरे राज्य के राजस्व से अधिक थी। यह अर्थशास्त्र को लूटना है।

अफसोस की बात है कि गोवा अकेला नहीं है। भारत में, हमने खनिजों में भारी नुकसान पाया है। ऑस्ट्रेलिया ने दो हज़ार से दो हज़ार और दस के दशक में, निकाले गए खनिजों के अस्सी प्रतिशत को खो दिया।

क्या हो रहा है?

[ट्रांज़ीशन के लिए रुकें]

गोवा में, लौह अयस्क का खनन जेब में होता है और पिछले साठ वर्षों से चल रहा है ।यह एक बड़ा नियोक्ता था लेकिन राज्य के वित्त में ज्यादा योगदान नहीं देता था। खनन उद्योग ने राजनीतिक

फंडिंग के माध्यम से राज्य की राजनीति को हमेशा नियंत्रित किया है ।पक्ष जुटाव और रिश्वत ने उन्हें लंबे समय तक कानून की अनदेखी करने में सक्षम बनाया ।

खनन क्षेत्रों में, खनन प्रभावित लोगों ने विरोध किया। खनिकों ने कुछ स्थानीय नेताओं को अधिक कीमत वाले ट्रक के कॉन्ट्रैक्ट देकर सह-चुनाव किया ।वे खनन पर निर्भर हो गए। स्थानीय आबादी विभाजित हो गई थी।

खनन क्षेत्रों के बाहर, सामान्य लोग खनन के पेशे और आय को सकारात्मक रूप में देखते हैं । वे स्थानीय अर्थव्यवस्था की बढ़त से लाभान्वित भी होते हैं। लेकिन वे यह नहीं देख पाते हैं कि उनके धन की चोरी हो रही है और उन्हें उनके वोट के लिए लॉलीपॉप दिया जा रहा है।

इसलिए खनन को खनिकों, कर्मचारियों, आश्रितों, स्थानीय नेताओं, राजनेताओं, नौकरशाही, आम जनता और नागरिक समाज का समर्थन प्राप्त है। हममें से कुछ जो खनन का विरोध करते हैं, वे "विकास विरोधी" हो जाते हैं। **हम इस पागलपन को कैसे रोकें?**

[जोर देने के लिए रुकें, पांच सिद्धांत स्लाइड]

पाँच सरल सिद्धांत!

सबसे पहले, प्राकृतिक संसाधनों का स्वामित्व राज्य के पास लोगों और विशेष रूप से भावी पीढ़ियों के एक ट्रस्टी के रूप में होता है।

दूसरा, जैसा कि हमने खनिजों को विरासत में लिया है, हमें भविष्य की पीढ़ियों को या तो खनिजों या उनके पूर्ण मूल्य के उत्तराधिकार को सुनिश्चित करना चाहिए।

तीसरा, **यदि हम** अपना खान खोदते हैं और खनिज बेचते हैं, **तो हमें शून्य हानि** सुनिश्चित करनी चाहिए ।हमें अपने खनिज का निष्कर्षण लागत के साथ संपूर्ण मूल्य, और खनिक के लिए एक सामान्य लाभ मिलना चाहिए।

चौथा, नॉर्वे की तरह, जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है उसे लोगों और विशेष रूप से भावी पीढ़ियों के लिए एक कोष में सहेजा जाना चाहिए।

पांचवां, हम खनिजों के मालिक हैं, हमारे पास फंड है, हम फंड से वास्तविक आय के मालिक हैं। अलास्का की तरह, समान रूप से सभी के स्वामित्व के अधिकार के रूप में हर एक नागरिक के लाभांश के रूप में आय को वितरित किया जाना चाहिए ।

शून्य हानि जमा नॉर्वे जमा अलास्का। हर कोई इसे समझता है और इससे सहमत है। लेकिन यह प्रणाली को कैसे बदलता है?

जब तक खनन एक स्थानीय मुद्दा है, तब तक राजनीतिक रूप से जीतना मुश्किल होगा। लाभांश कुंजी है।यह आम लोगों को उनके खनिजों से निर्मित फंड से जोड़ता है। राज्य में हर कोई नुकसान को रोकने के लिए एक नैतिक और वित्तीय हित के साथ एक हितधारक बन जाता है।

खदानों की निरंतर जांच की जाएगी। ओडिशा निर्णय किसी भी पर्यावरण कानून के उल्लंघन को अवैध खनन बनाता है।अवैध खनन चोरी है। कानून में अयस्क की वसूली या उसके पूर्ण मूल्य की आवश्यकता होती है।

खनन राजनेताओं के लिए सिरदर्द बन जाता है। सभी मतदाता नुकसान की निगरानी कर रहे हैं ।यहाँ बजट के लिए कोई पैसा नहीं है ।और लोग विरोध कर रहे हैं ।वे तय कर सकते हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जमीन में खनिजों को छोड़ना बेहतर होगा ।

[ट्रांज़ीशन के लिए रुकें]

हमारे मुकदमेबाजी में, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने खनन पर एक सीमा लगा दी और अंतरदेशीय साम्य के आधार पर एक स्थायी फंड का आदेश दिया। यह **प्रथम वैश्विक न्यायिक है।**

सीमा महत्वपूर्ण है। इसके दो कारण हैं। भविष्य की पीढ़ियों के लिए खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। दूसरे, कई खानों के होने पर होने वाली क्षति सीमित होती है।

कोर्ट ने फैसला सुनाया कि दो हजार सात के बाद सभी खनन अवैध होंगे। पांच साल बाद खनन बंद हो गया ।अवैध खनन चोरी है। पैंसठ हजार करोड़ का लौह अयस्क चोरी हो गया, प्रत्येक गोआ के नागरिक के लिए साढ़े तीन लाख, चार सदस्यो के एक परिवार के लिए चौदह लाख।

गोवा के चुनाव दो हज़ार सत्रह की शुरुआत में हुए थे। हमने एक व्यावहारिक घोषणा पत्र बनाया, जिसे हमने सभी दलों और उम्मीदवारों को अपनाने के लिए कहा ।हमें एक खनिक, एक खनन प्रभावित नेता और एक खनन आश्रित नेता का समर्थन मिला। प्रधान पादरी ने भी हमारा समर्थन किया।

कांग्रेस और भाजपा स्पष्ट रूप से खनिक के साथ थे ।लेकिन हमें उम्मीद थी कि एक भ्रष्टाचार विरोधी पार्टी हमारे घोषणापत्र को अपनाएगी।

आम आदमी पार्टी ने खनन भ्रष्टाचार को रोकने का वादा किया।दुर्भाग्य से, इसने खनन धन को वोट खर्च करने और जीतने के लिए एक बोनस के रूप में देखा। उन्होंने भारी सब्सिडी का वादा किया।

उन्होंने खनन को धन की बिक्री के रूप मे देखने से इनकार कर दिया ।क्यूं ?

[ट्रांज़ीशन के लिए रुकें]

सरकारी लेखा रॉयल्टी को "राजस्व" के रूप में मानते हैं और नुकसान का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं समझते है। अधिक खनन का अर्थ है अधिक राजस्व।

मान लीजिए सरकारों को मानना पड़ा कि खनन हमारी खनिज संपदा की बिक्री है। तब अधिक खनन से अधिक नुकसान होगा। राजस्व बचाना होगा ।

राजस्व को आय के रूप में मानना राजनेताओं और आम लोगों के द्वारा एक सुविधाजनक गलती है।

यह पहेली का अंतिम टुकड़ा था। हमने खनिजों को धन और खनन को उनकी बिक्री के रूप में अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानकों को बदलने के लिए एक वैश्विक अभियान शुरू किया

हमने रॉयल्टी को "राजस्व", "आय", "कर" या "कमाई" के रूप में पूरी तरह से रोकने के लिए एक सचेत प्रयास किया। हर बार जब हम रॉयल्टी "राजस्व" कहते हैं, तो हम अपने आप को मूर्ख बनाते

हैं और अपने बच्चों के धन की चोरी को सक्षम करते हैं। **हम सभी को यह भ्रम दूर करना चाहिए कि रॉयल्टी आय है** ।हम अपने खनिज बेच रहे हैं।

[ट्रांज़ीशन के लिए रुकें]

गोवा सरकार ने अवैध खननकर्ताओं को दिए गए लीज़ का नवीनीकरण किया था। गोवा फाउंडेशन और दो अन्य समूहों ने इसे चुनौती दी। दो हज़ार अठारह में, सुप्रीम कोर्ट ने खनन लीज़ के नवीनीकरण को रद्द कर दिया, और नए लीज़ के लिए कहा।

गोवा में खनन अभी भी बंद है ।हम अपने पैंसठ हजार करोड़ वापस चाहते हैं ।सरकार ने वसूली नहीं करने का फैसला किया है।सभी चालीस विधायकों ने खदानों को लीज़ वापस देने के लिए एमएमडीआर कानून में संशोधन की मांग की है ।लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है।

भारत की राष्ट्रीय खनिज नीति की समीक्षा की जा रही है। एक नागरिक समाज समूह को प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा गया । हमने खनिजों को एक साझा विरासत के रूप में तैयार किया है, सामूहिक संपत्ति जो चोरी से बचाई जानी चाहिए। इसके लिए एक कानूनी उद्देश्य, एक उच्च सुरक्षा मानसिकता, फिट और उचित व्यक्ति परीक्षणों के साथ-साथ कट्टरपंथी पारदर्शिता के रूप में शून्य हानि की आवश्यकता होती है।

तीन प्रमुख मंत्रालयों - वित्त, खनिज और पर्यावरण - ने स्वीकार किया है कि खनिज एक साझा विरासत हैं। राष्ट्रीय खनिज नीति का मसौदा कहता है :

“यह समझने की आवश्यकता है कि खनिजों सहित प्राकृतिक संसाधन एक साझा विरासत हैं, जहां राज्य लोगों की ओर से ट्रस्टी है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आने वाली पीढ़ियों को विरासत का लाभ मिले। राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगी कि निकाले गए खनिजों का पूरा मूल्य राज्य को प्राप्त हो।”

मसौदा नीति में खनिजों के वार्षिक उत्खनन की राज्य-वार / क्षेत्र-वार सीमा तय करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी निकाय का भी प्रस्ताव है।

आप जो भुगतान करते हैं उसकी घोषणा करे यह खनन पर एक वैश्विक नागरिक समाज गठबंधन है। मैंने हाल ही में जनवरी के अंत में अपनी महासभा में इन विचारों को प्रस्तुत किया। बहुपक्षीय विकास बैंकों सहित सरकारों, कंपनियों और अंतर-सरकारी संस्थाओं को स्वीकार करने और तलाशने के लिए उनके सांप्रदायिक आह्वान करते हैं, जहां नागरिक तेल, गैस और खनिजों को एक साझा अंतर-सरकारी विरासत के रूप में देखे जाने की अवधारणा की मांग करते हैं,;

और हमने आईएमएफ और अन्य लोगों के साथ खनिजों को हमारे धन और खनन को हमारीखनिजों की बिक्री मानने के बारे मे चर्चा की है। उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि इस बदलाव में कुछ समय लगेगा।

[ट्रांज़ीशन के लिए रुकें]

अंत मे, खनिज एक **साझा विरासत** , विशाल धन हैं।हमें भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसे बचाते हुए चोरों से अपने धन की रक्षा करनी चाहिए। यदि हम अपना कर्तव्य पूरा करते हैं, तो हम अपनी विरासत के फल का आनंद ले सकते हैं। कोई भी नुकसान हम सभी और हमारी आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए एक नुकसान है।

हमें **जिस भविष्य की आवश्यकता** है उसकी मांग में हमारे साथ शामिल हों !